लेटर्स पेटेंट अपील

डी. के. महाजन न्यायमूर्थु और एच. आर. सोढ़ी न्यायमूर्थी के समक्ष

हरियाणा राज्य, *बी टी सी , - अपीलकर्ता।*

बनाम

हरि सिंह, *आदि, - उत्तरदाता।*

1970 के लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 650

23 सितंबर, 1971

ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम (1948 का एल) - धारा 2 (8), 18 *और 46* - पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम*) नियम (1949*) - *नियम* 16 (एच) - *सामान्य उद्देश्यों के लिए भूमि का आरक्षण - क्या कार्यकारी निर्देशों द्वारा तय किया जा सकता है।*

ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1948 की धारा 18 में चकबंदी अधिकारी को कुछ आकस्मिकताओं में सामान्य उद्देश्य के लिए भूमि आरक्षित करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन जिस तरह से आरक्षण दिया जाना है वह नियम द्वारा निर्देशित और नियंत्रित है।

ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन निवारण) नियमावली की धारा 16(ii) 1949. इस नियम के तहत समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित पैमाने पर गांव के कॉमन पूल से जमीन आरक्षित की जा सकती है। अधिनियम की धारा 2 (जी) के तहत "निर्धारित" शब्द का अर्थ अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित है। इसलिए, अधिनियम द्वारा "निर्धारित" शब्द को एक अर्थ दिया गया है और यदि नियमों में एक ही अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है, तो इसे एक अलग अर्थ नहीं दिया जा सकता है जब तक कि सामग्री इसके विपरीत इंगित न करे या यह किसी भी प्रतिकूलता की ओर ले जाए। राज्य सरकार के पास धारा 46 (2) (ई) के तहत धारा 18 के तहत क्षेत्र को आरक्षित करने के तरीके के बारे में नियम बनाने की शक्ति है और संदेह से परे पैमाने के निर्धारण का मामला ऐसे आरक्षण के तरीके से संबंधित है। संभवतः यह इरादा नहीं किया जा सकता है कि पैमानों को कार्यकारी निर्देशों द्वारा तय किया जा सकता है, जबकि वास्तव में, ऐसे पैमानों का निर्धारण सामान्य उद्देश्यों के लिए भूमि के आरक्षण के संबंध में भूस्वामियों के लिए बहुत मूल्य और महत्व का है। कार्यकारी निर्देश नियमों का स्थान नहीं ले सकते हैं और समय-समय पर पैमानों को बदलने के लिए कार्यकारी निर्देशों की अनुमति देने वाली कोई भी व्याख्या अधिनियम की योजना के विपरीत होगी जो नियम बनाने का प्रावधान करती है क्योंकि एक क्षेत्र को सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित किया जाना है।

(पैरा 2 और 3)

माननीय न् यायमूर्ति ए डी कोशल द्वारा 29 मई, 1970 को सिविल रिट सं 2010-2012 में पारित आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खण्ड X के अंतर्गत लेटर्स पेटेंट अपील। 1970 का 615।

अपीलकर्ताओं की ओर से *हरियाणा के एडवोकेट-जनरल के वकील अशोक भान।*

उत्तरदाताओं के लिए *यू.डी. आईगौर, वकील।*

निर्णय

इस न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा दिया गया था -

(एक) इस पत्र पेटेंट अपील में निर्धारण के लिए उठने वाला एकमात्र प्रश्न ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन निवारण) नियम, 1949 के नियम 16 (ii) में प्रयुक्त "विहित" अभिव्यक्ति की व्याख्या से संबंधित है, जिसे बाद में ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन निवारण) अधिनियम की धारा 46 द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के तहत बनाए गए नियमों के रूप में संदर्भित किया गया है। 1948, इसके बाद इसे कहा गया। ढोंग।

(दो) चकबंदी द्वारा गांव बहलबा, तहसील गोहाना, जिला रोहतक के लिए जोतों के समेकन की योजना तैयार की गई थी।

अधिनियम की धारा 18 के तहत कथित तौर पर सामान्य उद्देश्यों के लिए 3220 कनाल 4 मरला का क्षेत्र आरक्षित किया गया था। 66 अधिकार धारकों ने इस योजना को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत इस न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और हमला मुख्य रूप से इस आधार पर निर्देशित किया गया कि उक्त आरक्षण नियम 16 (ii) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 18 का उल्लंघन था। इन प्रावधानों को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपने निर्णय में पुन: प्रस्तुत किया गया है, लेकिन संदर्भ की सुविधा के लिए उन्हें विस्तार से फिर से उद्धृत किया जा सकता है: -

धारा 18.

"सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि। इस समय लागू किसी भी कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, चकबंदी अधिकारी के लिए यह निर्देश देना विधिसम्मत होगा -

(अ) कि किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए विशेष रूप से सौंपी गई कोई भी भूमि इस तरह से सौंपी नहीं जाएगी और इसके स्थान पर किसी अन्य भूमि को आवंटित करना होगा;

(आ) राज्य के भीतर शिवालिक पर्वत श्रृंखला के माध्यम से या उससे बहने वाली धारा या धार के तल के नीचे की कोई भी भूमि किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए सौंपी जाएगी;

(इ) यदि चकबंदी के तहत किसी भी क्षेत्र में किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए कोई भूमि आरक्षित नहीं है, जिसमें गांव *की आबादी का विस्तार शामिल है,* या यदि इस तरह आरक्षित भूमि अपर्याप्त है, तो ऐसे उद्देश्य के लिए अन्य भूमि आवंटित करने के लिए।

नियम 16 (ii)

"एक एस्टेट या एस्टेट में जहां चकबंदी की कार्यवाही के दौरान कोई *शामलात* देह भूमि नहीं है या ऐसी भूमि को अपर्याप्त माना जाता है, भूमि को ग्राम पंचायत के लिए और अन्य सामान्य उद्देश्यों के लिए, अधिनियम की धारा 18 (सी) के तहत, समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित पैमाने पर गांव के सामान्य पूल से आरक्षित किया जाएगा। इस प्रकार आरक्षित भूमि के संबंध में मालिकाना अधिकार (*आबादी* मालिकों और गैर-मालिकों के विस्तार के लिए आरक्षित क्षेत्र को छोड़कर) संबंधित संपत्ति या सम्पदा के स्वामित्व निकाय में निहित होंगे और इसे अधिकारों के रिकॉर्ड के स्वामित्व के कॉलम में दर्ज किया जाएगा (जुमला मलकान वा दिगार हकदरन अराजी हसब रसाद रकबा)। ऐसी भूमि का प्रबंधन राज्य की पंचायत द्वारा किया जाएगा।

ग्राम स्वामित्व निकाय और पंचायत की ओर से संबंधित संपत्ति या सम्पदा को सामान्य आवश्यकताओं और संबंधित संपत्ति के लाभों के लिए आरक्षित भूमि से प्राप्त आय का उपयोग करने का अधिकार होगा।

इस स्तर पर धारा 46 (2) (सी) को संदर्भित करना भी उपयोगी होगा जो नियम बनाने की शक्ति देता है। यह प्रावधान निम्नानुसार है :-

"46(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकती है-

* * *

(उ) जिस तरह से धारा 18 के तहत क्षेत्र को आरक्षित किया जाना है और जिस तरह से इससे निपटा जाना है और जिस तरह से गांव की *आबादी* को मुआवजे के भुगतान पर मालिकों और गैर-मालिकों (अनुसूचित

जाति, सिख पिछड़ा वर्ग, कारीगरों और मजदूरों सहित) को दिया जाना है।

धारा 2 (जी) "निर्धारित" अभिव्यक्ति को निम्नानुसार परिभाषित करती है: –

"निर्धारित" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित;

धारा 18 निश्चित रूप से चकबंदी अधिकारी को कुछ आकस्मिकताओं में सामान्य उद्देश्य के लिए भूमि आरक्षित करने का अधिकार देती है, लेकिन जिस तरह से आरक्षण किया जाना है, वह नियम 16 (ii) द्वारा निर्देशित और नियंत्रित है। इस नियम को पढ़ने से पता चलता है कि एक एस्टेट या एस्टेट में जहां चकबंदी की कार्यवाही के दौरान कोई *शामलात* देह नहीं है या ऐसी भूमि को अपर्याप्त माना जाता है, वहां ग्राम पंचायत के लिए और अन्य सामान्य उद्देश्यों के लिए, गांव के सामान्य पूल से भूमि आरक्षित की जानी चाहिए, और ऐसे आरक्षण का पैमाना सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

(तीन) हमारे समक्ष यह एक समान आधार है कि राज्य सरकार द्वारा जारी कार्यकारी अनुदेशों द्वारा एक पैमाना निर्धारित किया गया है लेकिन नियमों के तहत निर्धारित नहीं किया गया है। राज्य की ओर से तर्क यह है कि नियम 16 (ii) में प्रयुक्त "निर्धारित" शब्द को वह अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए जो उसे अधिनियम की धारा 2 (जी) द्वारा सौंपा गया है और नियमों के तहत जो कुछ आवश्यक है वह यह है कि कुछ पैमाने तय किए जाने चाहिए। दूसरे शब्दों में, विवाद यह है कि नियम बनाने वाले प्राधिकरण द्वारा यह इरादा नहीं किया जा सकता है कि हर बार एक पैमाना तय किया जाना है या

नियमों में बदलाव किया जाए। हमें डर है कि इस विवाद में कोई दम नहीं है। अधिनियम द्वारा "निर्धारित" शब्द को एक अर्थ दिया गया है और यदि नियमों में एक ही अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है, तो इसे एक अलग अर्थ नहीं दिया जा सकता है जब तक कि संदर्भ इसके विपरीत नहीं है या यह किसी भी प्रतिकूलता की ओर जाता है। राज्य सरकार के पास धारा 46 (2) (ई) के तहत नियम बनाने की शक्ति है कि धारा 18 के तहत क्षेत्र को किस तरीके से आरक्षित किया जाना है और संदेह से परे पैमाने के निर्धारण का मामला ऐसे आरक्षण के तरीके से संबंधित है। संभवतः यह इरादा नहीं किया जा सकता है कि पैमानों को कार्यकारी निर्देशों द्वारा तय किया जा सकता है, जबकि वास्तव में, ऐसे पैमानों का निर्धारण सामान्य उद्देश्यों के लिए भूमि के आरक्षण के संबंध में भूस्वामियों के लिए बहुत मूल्य और महत्व का है। कार्यकारी अनुदेश नियमों का स्थान नहीं ले सकते हैं और समय-समय पर पैमानों को बदलने के लिए कार्यकारी निर्देशों की अनुमति देने वाली कोई भी व्याख्या अधिनियम की योजना के विपरीत होगी जो उस तरीके के लिए नियम बनाने का प्रावधान करती है जिसमें किसी क्षेत्र को सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित किया जाना है। इस संबंध में पंजाब सामान्य खंड अधिनियम की धारा 18 का संदर्भ अनुचित नहीं है और यह निम्नानुसार है :-

> "जहां, किसी भी पंजाब अधिनियम द्वारा, कोई अधिसूचना, आदेश, योजना, नियम, फॉर्म या उप-कानून जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है, तो अधिसूचना, आदेश, योजना, नियम, फॉर्म या उप-कानून में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्तियां, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो, के समान संबंधित अर्थ होंगे, जो अधिनियम में शक्ति प्रदान करते हैं।

यह प्रावधान फिर से दर्शाता है कि किसी भी अधिनियम में प्रयुक्त अभिव्यक्ति, या उसके तहत बनाए गए नियमों को समान अर्थ दिया जाना चाहिए।

(चार) गंडा सिंह *बनाम* नरूला जे. *पंजाब राज्य और अन्य* (1) को धारा 18 (सी) और नियम 16 (ii) पर विचार करने का अवसर मिला। विद्वान न्यायाधीश के समक्ष एक विवाद उठाया गया था कि क्या नियम 16 (ii) द्वारा विचार किए गए आरक्षण का पैमाना निर्धारित किया गया था या नहीं। पक्षकारों की बातों के संदर्भ में, विद्वान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यद्यपि आरक्षण सामान्य पूल से सामान्य उद्देश्यों के लिए किया गया था, लेकिन सरकार द्वारा ऐसा कोई पैमाना निर्धारित नहीं किया गया था, जैसा कि राज्य के वकील द्वारा आग्रह किया गया था। यह प्राधिकरण तत्काल मामले में बिंदु को सीधे कवर नहीं करता है।

(1) 1966-68 पी.एल.आर.

(पाँच) फिर से, बी.आर. तुली न्यायमूर्ती , *पुराण और अन्य बनाम अन्य मामले में दिया* गया निर्णय। *हरियाणा राज्य और अन्य (2) परोक्ष* रूप से इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं कि आरक्षण नियम 16 (ii) के तहत निर्धारित किया जाना चाहिए, लेकिन इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है।

(छः) इस मुद्दे पर केवल आर. एस. सरकारिया जे. ने *बूल सिंह बनाम भारत मामले में विचार किया* है। *पंजाब राज्य और अन्य* (3), जहां यह देखा गया है कि "केवल एक कार्यकारी आदेश द्वारा पैमाने का पर्चेपन, जैसा कि एक वैधानिक नियम से अलग है, नियम 16 (ii) के चिंतन के भीतर पैमाने का वैध नुस्खा नहीं है, और इसलिए, इसे अनदेखा किया जाना चाहिए।

(सात) हम उपरोक्त मामले में सरकारिया जे के दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक सहमत हैं और हमें यह मानना चाहिए कि आरक्षण के लिए पैमाना नियमों में ही निर्धारित किया जाना चाहिए और यह नहीं कि इसे कार्यकारी निर्देशों द्वारा तय किया जा सकता है।

(आठ) पूर्वगामी कारणों से, अपील में कोई दम नहीं है जिसे लागत के बारे में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया गया है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा |

अमृतबीर कौर
प्रक्षिशु न्यायिक अधिकारी
अससंघ, कर्नल
हरियाणा